आज का मौसम

अधिकतम 37° C
न्यूनतम 20° C
सूर्य अस्त (आज) 6:10
सूर्य उदय (कल) 6:39

दैनिक समाचार पत्र

# जीत समाचार

जीत सच्ची खबर की

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश

वीरवार
02 अप्रैल 2026

वर्ष : 13 | अंक : 193 | मूल्य : 2 रू | पृष्ठ : 8 | RNI NO : PUNHIN/2013/60106 | www.zeetsamachar.com

**अनमोल वचन**

"एक प्राचीन कहावत हैं जो पेड़ तूफानों में झुक जाते है वही बच जाते हैं, परमात्मा के सान्निध्य में रहों तुम्हे इसका अर्थ स्वयं समझ आ जायेगा।"

## संक्षिप्त न्यूज

### नालंदा मंदिर में भगदड़, 8 महिलाओं की मौतय जांच के लिए SIT गठित

नालंदा/बिहार एजेंसी 1 अप्रैल 2026। बिहार के नालंदा जिले में 1 अप्रैल 2026 को मां शीतला मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने से 8 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंचे थे। भीड़ बढ़ने के दौरान अचानक भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। देखते ही देखते कई लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े। हादसे में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया।

मुख्यमंत्री ने जताया दुख : हादसे पर बिहार सरकार ने गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के साथ घटना के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए गए।

विशेष जांच दल करेगी हादसे की जांच : सरकार ने घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल गठित किया है। विशेष जांच दल यह पता लगाएगी कि धार्मिक आयोजन के दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे और भगदड़ की स्थिति कैसे बनी।

जांच में मंदिर परिसर की व्यवस्था, प्रवेश एवं निकास मार्ग, पुलिस बल की तैनाती, भीड़ प्रबंधन और आयोजन से जुड़े प्रशासनिक इंतजामों की भी समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल : हादसे के बाद धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी।

प्रशासन ने भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान भीड़ नियंत्रण को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मंदिर और आयोजन स्थलों पर प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग रास्ते, पर्याप्त पुलिस बल और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

मृतकों के परिवारों में मातम : हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। अस्पतालों में परिजन अपनों की जानकारी लेने के लिए पहुंचे। प्रशासन की ओर से मृतकों की पहचान और पोस्टमार्टम संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की गई।

# नया आयकर कानून लागू, फास्टैग पास महंगाय डिजिटल भुगतान और पैन से जुड़े नियमों में भी बदलाव

**संवाद न्यूज एजेंसी**

नई दिल्ली 1 अप्रैल 2026। देश में नए वित्तीय वर्ष 2026–27 की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2026 से आम लोगों, कारोबारियों और करदाताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं। नए वित्त वर्ष के पहले दिन से नया आयकर कानून लागू होने के साथ एलपीजी,फास्टैग, पैन और डिजिटल भुगतान से जुड़े नियमों में भी बदलाव प्रभावी हो गए। इन बदलावों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं और कारोबारियों की जेब पर पड़ने की संभावना है।

सबसे बड़ा बदलाव आयकर अधिनियम 2025 के लागू होने के रूप में हुआ है। नया कानून 1961 के आयकर कानून की जगह ले रहा है। इसका उद्देश्य आयकर से जुड़े प्रावधानों को अधिक सरल और व्यवस्थित बनाना तथा करदाताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाना है। पुराने वर्षों से संबंधित आकलन और लंबित कार्यवाही पुराने कानून के प्रावधानों के अनुसार ही जारी रहेगी।

कर वर्ष की नई व्यवस्था : नए आयकर कानून के साथ 'कर वर्ष' की व्यवस्था भी लागू हुई है। अब 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली कर अवधि को कर वर्ष 2026–27 के रूप में देखा जाएगा। इससे पहले इस्तेमाल होने वाली पिछले वर्ष और आकलन वर्ष की अलग-अलग शब्दावली को सरल करने का प्रयास किया गया है।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा : 1 अप्रैल से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और छोटे कारोबारों पर पड़ सकता है।एलपीजी की बढ़ी लागत के कारण खाद्य पदार्थों और अन्य सेवाओं की कीमतों पर भी दबाव आने की संभावना जताई जा रही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तत्काल उसी अनुपात में बदलाव नहीं किया गया।

फास्टैग और सालाना पास भी महंगा : हाईवे पर सफर करने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए फास्टैग और सालाना पास की कीमत बढ़ाकर 3,075 कर दी गई है। इससे पहले इसकी फीस 3,000 थी। वार्षिक पास की कीमत में हुई वृद्धि का असर उन वाहन मालिकों पर पड़ेगा जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित यात्रा करते हैं।

डिजिटल भुगतान में सुरक्षा बढ़ी : डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था लागू की गई है। ऑनलाइन लेन-देन के दौरान अतिरिक्त प्रमाणीकरण से साइबर धोखाधड़ी और अनधिकृत भुगतान को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

पैन से जुड़े नियमों में बदलाव : नए वित्त वर्ष के साथ पैन कार्ड के आवेदन और उसमें बदलाव से जुड़े नियमों में भी संशोधन लागू हुआ। सरकार का उद्देश्य पैन से जुड़ी जानकारी को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना तथा पहचान संबंधी धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है।

आम आदमी की जेब पर मिला-जुला असर : 1 अप्रैल से लागू हुए बदलावों का असर अलग-अलग वर्गों पर अलग होगा। कमर्शियल एलनपीजी महंगा होने से कारोबारियों की लागत बढ़ेगी, जबकि फास्टैग पास की कीमत बढ़ने से नियमित हाईवे यात्रियों पर अतिरिक्त खर्च आएगा। दूसरी ओर, नए आयकर और डिजिटल भुगतान संबंधी प्रावधानों का उद्देश्य कर व्यवस्था और ऑनलाइन लेन-देन को अधिक व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाना है।

# कोलकाता में ईडी की कार्रवाई, वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो ठिकानों पर छापेमारी

**संवाद न्यूज एजेंसी**

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अप्रैल 2026 को कोलकाता में कथित वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए बालीगंज इलाके के दो ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी की कार्रवाई देर तक जारी रही।

प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई कथित जबरन वसूली से जुड़े धन के लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित तौर पर वसूली से प्राप्त धन का इस्तेमाल और हस्तांतरण किस तरह किया गया।

इसी मामले की आगे की जांच में जमीन कब्जाने, अवैध निर्माण और रियल एस्टेट से जुड़े लेन-देन के आरोप भी सामने आए हैं। 1 अप्रैल को सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में छह स्थानों पर भी तलाशी की, जिनमें कथित इतिहासशीटर बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू और उसके सहयोगियों से जुड़े ठिकाने शामिल थे।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में कथित तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि रियल एस्टेट गतिविधियों की आड़ में वसूली से प्राप्त रकम को किन लोगों या संस्थाओं तक पहुंचाया गया। एजेंसी संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है।

अधिकारियों के अनुसार जांच अभी जारी है और तलाशी के दौरान सामने आने वाली सामग्री के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल एजेंसी की ओर से जांच के सभी निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

# राज्यसभा में सीएपीएफ विधेयक पर चर्चा, सरकार ने बताया आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने वाला कदम

**संवाद न्यूज एजेंसी**

नई दिल्ली। राज्यसभा में 1 अप्रैल 2026 को सीएपीएफ बिल, 2026 पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को सदन में विचार और पारित करने के लिए रखा। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नियमों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है।

विधेयक के दायरे में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी शामिल हैं। प्रस्तावित

व्यवस्था में इन बलों के ग्रुप-ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़े मामलों को विनियमित करने का प्रावधान है।

वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति : विधेयक में वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रावधान भी हैं। इसके अनुसार आईजी स्तर के कुल पदों में 50 प्रतिशत, एडीजी स्तर के कम से कम 67 प्रतिशत पद तथा सभी स्पैशल डीजी और डीजी पद आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान है।

विपक्ष ने उठाए सवाल : विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई और इसे संसदीय समिति को भेजने की मांग की। विपक्ष का कहना था कि वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से सीएआरएफ के अपने कैडर अधिकारियों की पदोन्नति और करियर संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। चर्चा के दौरान इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद सामने आए।

ध्वनिमत से विधेयक पारित : चर्चा के बाद राज्यसभा ने सीएआरपीएफ बिल, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विरोध जताते हुए विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य सीएपीएफ अधिकारियों की सेवा शर्तों में स्पष्टता और एकरूपता लाने के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।

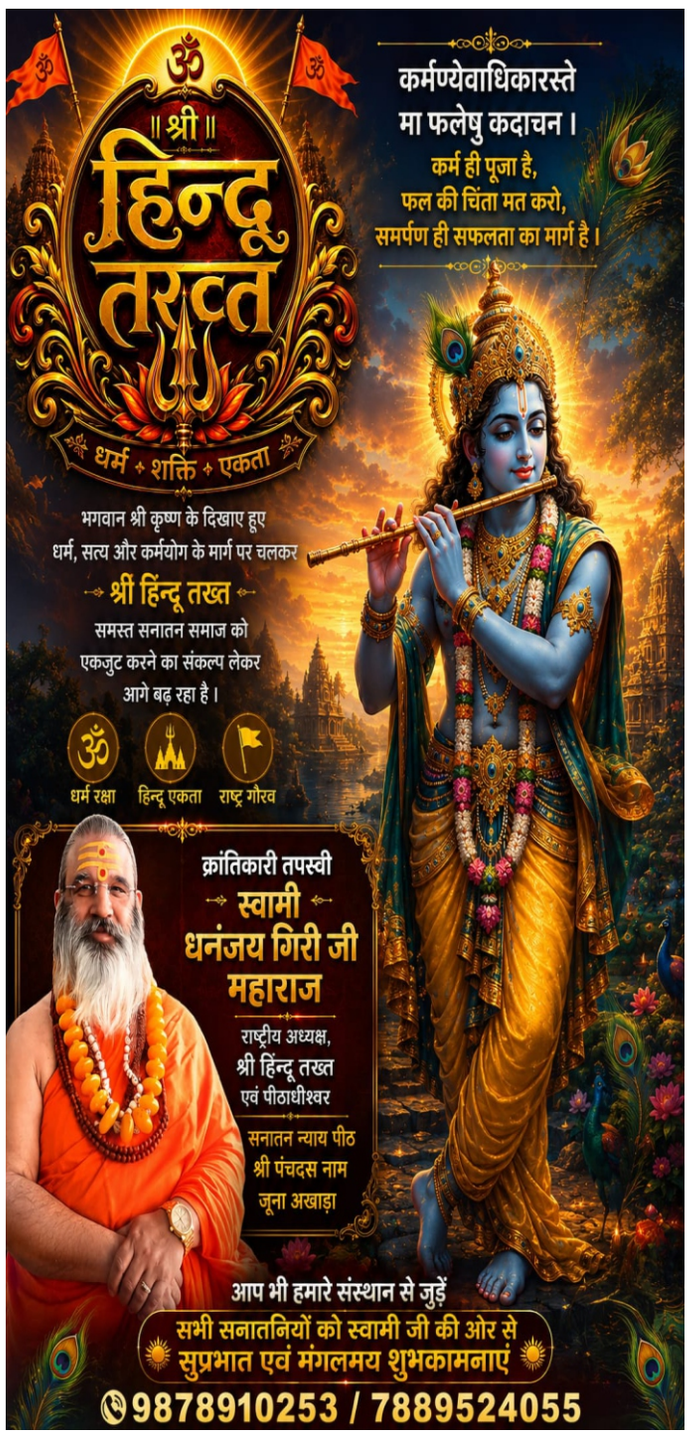


# जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ के पार, मार्च में 8.8 फीसदी बढ़ा राजस्व

**संवाद न्यूज एजेंसी**

नई दिल्ली 1 अप्रैल 2026। देश की अर्थव्यवस्था के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत मजबूत राजस्व आंकड़ों के साथ हुई है। मार्च 2026 में सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। मार्च में कुल सेवा कर राजस्व में सालाना आधार पर करीब 8.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। यह लगातार मजबूत कर संग्रह की तस्वीर पेश करता है और सरकार के राजस्व आधार के विस्तार का संकेत देता है।

मार्च महीने का सेवा कर संग्रह 2 लाख करोड़ से अधिक रहना कारोबार और खपत से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त वर्ष के अंतिम महीने में आम तौर पर कर संग्रह में तेजी देखी जाती है, क्योंकि कंपनियां और कारोबारी सालाना खातों को अंतिम रूप देते हैं तथा लंबित कर देनदारियों का निपटारा करते हैं।

**नए वित्त वर्ष की शुरुआत मजबूत आंकड़ों से :** 1 अप्रैल 2026 से वित्त वर्ष 2026–27 शुरू हो गया है। ऐसे समय में मार्च के मजबूत सेवा करआंकड़े सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं। सेवा कर संग्रह में वृद्धि से केंद्र और राज्यों दोनों को राजस्व प्राप्त होता है, जिससे विकास योजनाओं और सार्वजनिक खर्च के लिए वित्तीय संसाधन मजबूत होते हैं।

अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, औद्योगिक गतिविधियों, परिवहन, निर्माण और उपभोक्ता खर्च में होने वाले बदलाव का असर सेवा कर संग्रह पर पड़ता है। इसलिए कर संग्रह के आंकड़ों को आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख संकेतकों में से एक माना जाता है।

**सरकार के लिए बढ़ा राजस्व आधार :** सेवा कर व्यवस्था लागू होने के बाद कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और कर चोरी रोकने के लिए डिजिटल निगरानी एवं डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। फर्जी बिलिंग और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कार्रवाई से भी राजस्व संग्रह को मजबूत करने में मदद मिली है।

विशेषज्ञों के अनुसार सेवा कर संग्रह का २ लाख करोड़ से ऊपर बने रहना अर्थव्यवस्था में औपचारिक लेन-देन के विस्तार का संकेत हो सकता है। हालांकि, वास्तविक आर्थिक मजबूती का आकलन करने के लिए औद्योगिक उत्पादन, उपभोग, निर्यात और निवेश जैसे अन्य आंकड़ों को भी साथ में देखना जरूरी है।

**राज्यों को भी फायदा :** सेवा कर से मिलने वाला राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच साझा होता है। इसलिए संग्रह में वृद्धि का लाभ राज्यों को भी मिलता है। अधिक राजस्व से राज्य सरकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय गुंजाइश मिल सकती है।

# पश्चिम एशिया संकट से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

**संवाद न्यूज एजेंसी**

नई दिल्ली 1 अप्रैल 2026। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। क्षेत्र में अस्थिरता और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोखिम के कारण कच्चे तेल, स्च्ळ और स्छळ की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखने और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों को मजबूत करने के कदम तेज कर दिए हैं।

1 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की विशेष बैठक हुई। बैठक में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम से पैदा हुई स्थिति और देश में पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी, एलएनजी तथा बिजली की उपलब्धता की समीक्षा की गई। सरकार के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखना प्राथमिकता है।

**एलपीजीकी आपूर्ति पर विशेष नजर :** सरकार ने बताया कि एलपीजी की खरीद के लिए आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाई जा रही है और अलग-अलग देशों से नए एलपीजी तथा एलएनजी आपूर्ति स्रोत तलाशे जा रहे हैं। घरेलू एलपीजी की कीमतों को स्थिर रखने और देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और तेल कंपनियों को लगातार स्थिति की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने लोगों से एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की अनावश्यक खरीद या जमाखोरी से बचने की अपील की है। सरकार का कहना है कि पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और नागरिकों को केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए।

**कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव :** पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल एवं गैस उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत अपनी घरेलू जरूरतों का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी का असर देश के आयात बिल, रुपये की विनिमय दर और महंगाई पर पड़ सकता है।

सरकार ने संकट के बीच रिफाइनरियों के संचालन और पेट्रोल-डीजल के स्टॉक की भी समीक्षा की है। बाद की सरकारी जानकारी के अनुसार देश की रिफाइनरियां ऊंची क्षमता पर काम कर रही थीं और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के प्रयास किए गए। घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

**बिजली आपूर्ति को लेकर भी तैयारी :** ऊर्जा संकट का असर केवल पेट्रोलियम और गैस तक सीमित नहीं है। सरकार ने बिजली क्षेत्र की स्थिति की भी समीक्षा की है। 1 अप्रैल को हुई सीसीएस बैठक में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा हुई। सरकार के अनुसार देश में बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त कोयला भंडार उपलब्ध है।

**आम लोगों से ऊर्जा बचाने की अपील :** सरकार ने संकट की स्थिति में नागरिकों से ऊर्जा की बचत करने की अपील की है। जहां संभव हो, पीएनजी, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित किया गया है। स्च्ळ की अनावश्यक बुकिंग और पेट्रोल-डीजल की घबराहट में खरीदारी से बचने की सलाह भी दी गई है।

**भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है संकट? :** भारत की अर्थव्यवस्था में कच्चे तेल और गैस की अहम भूमिका है। परिवहन, उद्योग, बिजली, उर्वरक और घरेलू रसोई समेत कई क्षेत्र ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं। ऐसे में पश्चिम एशिया में लंबे समय तक अस्थिरता रहने पर तेल और गैस की कीमतों के साथ-साथ माल ढुलाई, उत्पादन और दैनिक उपभोग की लागत पर भी दबाव बढ़ सकता है।

हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि देश में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत, घरेलू उत्पादन और रणनीतिक प्रबंधन पर काम किया जा रहा है। सरकार स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है ताकि वैश्विक संकट का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर कम से कम पड़े।

## डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर -
## 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।'

# पंजाब में कानून-व्यवस्था और गैंगस्टर नेटवर्क -राज्य के सामने बड़ी चुनौती

पंजाब लंबे समय से कानून-व्यवस्था और संगठित अपराध की चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में गैंगस्टर नेटवर्क, नशा तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई, फिरौती, लक्षित हत्याओं और सीमा पार से होने वाली आपराधिक गतिविधियों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। हालांकि पंजाब पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) लगातार इन नेटवर्कों पर कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी बदलते तौर-तरीकों के कारण यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है।

पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसका फायदा उठाकर कई बार ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थ, हथियार और गोला-बारूद भेजने के प्रयास किए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियां नियमित रूप से ऐसे ड्रोन को पकड़ने और तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के अभियान चलाती हैं। इन गतिविधियों का सीधा संबंध कई बार संगठित अपराध और गैंगस्टर गिरोहों से भी जोड़ा जाता है।

गैंगस्टर नेटवर्क अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कई मामलों में विदेशों में बैठे अपराधी सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉलिंग और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए अपने नेटवर्क का संचालन करते हैं। वे रंगदारी वसूलने, धमकी देने और आपराधिक घटनाओं की साजिश रचने के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं। इससे पुलिस के सामने जांच और अपराध नियंत्रण की चुनौती और बढ़ जाती है।

राज्य में समय-समय पर गैंगवार, फिरौती, कारोबारियों को धमकियां, अवैध हथियारों की बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारियों की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इन घटनाओं से आम जनता में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती है और व्यापारिक माहौल पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सरकार और पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है।

पंजाब पुलिस ने हाल के वर्षों में कई बड़े अभियान चलाकर गैंगस्टर नेटवर्क पर शिकंजा कसने का दावा किया है। विशेष ऑपरेशन सेल, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स , साइबर विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों के सहयोग से अनेक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अवैध हथियारों की बरामदगी, बैंक खातों की जांच, संपत्तियों पर कार्रवाई और वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं।

नशा तस्करी और गैंगस्टर नेटवर्क के बीच संबंध भी चिंता का विषय है। जांच एजेंसियों का मानना है कि कई आपराधिक गिरोह नशे के कारोबार से आर्थिक लाभ प्राप्त कर अपने नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इसलिए नशे के खिलाफ अभियान और गैंगस्टर नेटवर्क पर कार्रवाई को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पुलिस कार्रवाई से इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए युवाओं को रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल सुविधाएं, कौशल विकास और नशामुक्ति कार्यक्रमों से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। समाज, परिवार, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासन को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा, जिससे युवा अपराध और नशे से दूर रहें।

इसके अलावा आधुनिक तकनीक का उपयोग, बेहतर खुफिया तंत्र, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, राज्यों के बीच समन्वय और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाकर संगठित अपराध पर अधिक प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

निष्कर्ष : कानून-व्यवस्था और गैंगस्टर नेटवर्क पंजाब के सामने एक गंभीर चुनौती हैं, लेकिन लगातार पुलिस कार्रवाई, सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय और समाज के सहयोग से इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में प्रयास जारी हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिए अपराध नियंत्रण के साथ-साथ युवाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

**कमल पवार (सम्पादक)**

# आज की प्रमुख हस्ती

## बच्चों में मोबाइल का बढ़ता दुरुपयोग: ज्ञान से अधिक मनोरंजन की ओर बढ़ते कदम

अजय कुमार
(एम.ए. राजनीति शास्त्र एवं बी. एड )
जिला कॉंगड़ा हिमाचल प्रदेश

आज का युग डिजिटल तकनीक का युग है। मोबाइल फोन ने शिक्षा, संचार और जानकारी प्राप्त करने के अनेक नए अवसर प्रदान किए हैं। यदि इसका सही उपयोग किया जाए, तो यह बच्चों के लिए ज्ञान का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। कोरोना महामारी के दौरान अहनलाइन कक्षाओं और घर से पढ़ाई की आवश्यकता के कारण बच्चों के हाथों में मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरण बड़ी संख्या में पहुँचे। उस समय यह शिक्षा का आवश्यक साधन था, लेकिन महामारी समाप्त होने के बाद भी अनेक बच्चों में मोबाइल के अत्यधिक उपयोग की आदत बनी रही।

आज अधिकांश बच्चे मोबाइल का उपयोग पढ़ाई और सीखने की अपेक्षा मनोरंजन, ऑनलाइन गेम, शॉर्ट वीडियो और सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने के लिए कर रहे हैं। यह स्थिति अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के लिए चिंता का विषय बन चुकी है।मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँखों की समस्या, नींद में कमी, एकाग्रता में गिरावट और शारीरिक गतिविधियों में कमी जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। कई बच्चे परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने के बजाय आभासी दुनिया में अधिक व्यस्त रहने लगे हैं। इससे उनके व्यवहार, अध्ययन और व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

विडंबना यह है कि जिस मोबाइल में विश्वभर का ज्ञान उपलब्ध है, उसका उपयोग बहुत कम बच्चे सीखने के लिए करते हैं। यदि प्रतिदिन कुछ समय शैक्षिक वीडियो, ई-पुस्तकों, विज्ञान, भाषा, सामान्य ज्ञान और नई तकनीकों को सीखने में लगाया जाए, तो मोबाइल एक उत्कृष्ट शिक्षक बन सकता है। दुर्भाग्य से अधिकांश समय मनोरंजन में ही व्यतीत हो जाता है।

इस समस्या का समाधान केवल बच्चों से अपेक्षा करने से नहीं होगा। अभिभावकों और शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की उचित सीमा तय करनी चाहिए, पढ़ाई, खेल-कूद और पारिवारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना चाहिए तथा उन्हें मोबाइल का सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग सिखाना चाहिए। साथ ही, बड़े भी स्वयं जिम्मेदारी से मोबाइल का उपयोग कर बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें।

मोबाइल न तो पूरी तरह अच्छा है और न ही बुरा। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस उद्देश्य से करते हैं। यदि बच्चे मोबाइल को ज्ञान, रचनात्मकता और कौशल विकास का साधन बनाएँ, तो वही तकनीक उनके उज्ज्वल भविष्य का आधार बन सकती है। लेकिन यदि इसका अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग जारी रहा, तो यह उनके बचपन, शिक्षा और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

आज आवश्यकता मोबाइल छोड़ने की नहीं, बल्कि मोबाइल का सही, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग सीखने और सिखाने की है। यही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है।

## महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर (भारत)

### 1. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (पुलिस, फायर, और एंबुलेंस)

| | |
|---|---|
| 112 | आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (पुलिस, फायर, और एंबुलेंस) |
| 100 | पुलिस (Police) |
| 101 | फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) |
| 102 / 108 | एम्बुलेंस सेवा (Ambulance) |
| 1091 | महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) |
| 1098 | चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline) |
| 104 | स्वास्थ्य हेल्पलाइन (Health Helpline/Medical Advice) |
| 1915 | पर्यटन हेल्पलाइन (Tourist Helpline) |
| 1930 | साइबर अपराध (Cyber Crime) |
| 139 | रेलवे पूछताछ / सुरक्षा (Railway Enquiry / Security) |
| 1363 | पर्यटन हेल्पलाइन (Tourist Helpline) |
| 1033 | सड़क दुर्घटना या राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकाल (Road Accident / National Highway Emergency) |
| 14567 | बुजुर्ग हेल्पलाइन (Elder Line) |
| 1551 | किसान कॉल सेंटर (Kisan Call Center) |
| 1906 | गैस सिलेंडर (LPG) रिसाव या आपातकाल (LPG Gas Leak / Emergency) |

### 2. राज्य / बिजली बोर्ड हेल्पलाइन नंबर (टोल-फ्री)

| राज्य | हेल्पलाइन नंबर (टोल-फ्री) | वैकल्पिक संपर्क नंबर / वेबसाइट |
|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश (HPSEBL) | 1912 | 1800-180-8060 \| www.hpseb.in |
| उत्तर प्रदेश (UPPCL / अन्य) | 1912 | 1800-180-8752 \| www.uppcl.org |
| दिल्ली (BSES/TPDDL) | 1912 | वेबसाइट के माध्यम से चैटबॉट सपोर्ट www.bsesdelhi.com / www.tatapower-ddl.com |
| पंजाब (PSPCL) | 1912 | 1800-180-1512 \| www.pspcl.in |
| हरियाणा (DHBVN/UHBVN) | 1912 | 1800-180-1833 \| www.dhbvn.org.in / www.uhbvn.com |
| मध्य प्रदेश (MPPKVVCL) | 1912 | 1800-233-1266, WhatsApp: 9425807257 www.mpez.co.in |
| उत्तराखंड (UPCL) | 1912 | 1800-419-0405 \| www.upcl.org |

### 3. राज्यवार जल हेल्पलाइन नंबर

| राज्य / विभाग | हेल्पलाइन नंबर | विवरण / वेबसाइट |
|---|---|---|
| केंद्रीय / राष्ट्रीय | 1800-121-2164 | जल जीवन मिशन का टोल-फ्री नंबर \| www.jaljeevanmission.gov.in |
| हिमाचल प्रदेश (स्थानीय) | 1800-180-8009, 1100 | जल शक्ति विभाग (SNK), शिकायत निवारण केंद्र |
| दिल्ली | 1916 | दिल्ली जल बोर्ड (24x7) \| www.delhijalboard.nic.in |
| उत्तर प्रदेश | 1076 | सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) \| www.up.gov.in |
| बिहार | 1800-123-1121 | पीएचईडी (PHED) पेयजल शिकायत \| www.prdbihar.gov.in |
| राजस्थान | 1800-180-6088 | जलदाय विभाग (PHED) \| www.jalday.rajasthan.gov.in |
| मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (सभी राज्य) | 181 या 1902 | सभी राज्यों की शिकायत और जानकारी के लिए |

### 4. राज्यवार परिवहन (बस) हेल्पलाइन नंबर

| राज्य / निगम | हेल्पलाइन नंबर | विवरण / उपयोग |
|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश (HRTC) | 1100, 1800 180 8185 | 24/7 हेल्पलाइन, पूछताछ और शिकायत निवारण |
| दिल्ली (DTC) | 011-22968836 | आईएसबीटी (ISBT) पूछताछ |
| उत्तर प्रदेश (UPSRTC) | 149, 1800 1800 151 | 24/7 टोल-फ्री सुविधा |
| राजस्थान (RSRTC) | 181 | मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता |
| चंडीगढ़ (CTU) | 1800 274 7400 | टोल फ्री नंबर |

इन हेल्पलाइन नंबरों को सेव करें और जरूरत पड़ने पर उपयोग करें। यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दैनिक समाचार पत्र
जीत समाचार
जीत सच्ची ख़बर की

मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक : कमल पवार द्वारा 11368, पवित्र नगर, वालिया कालोनी हैबोवाल कलां, लुधियाना से प्रकाशित एंव जीत लुधियाना प्रिंटर्स हैबोवाल लुधियाना से मुद्रित।

सम्पादक : कमल पवार इस अंक मे प्रकाशित एंव समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा उत्पन्न समस्त विवाद लुधियाना न्यायालय के अधीन होगे।

R.N.I NO. PUN/HIN/2013/60106

Contact us :- +91-98030-25111.

# हरियाणा में जमीन-जायदाद के कलेक्टर रेट बदले, खरीदारी होगी महंगी

जीत समाचार ब्यूरों हरियाणा। हरियाणा में नए वित्तीय वर्ष 2026–27 की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2026 से संशोधित कलेक्टर रेट लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने जमीन, आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के सरकारी मूल्य को बाजार में चल रहे वास्तविक लेन-देन के करीब लाने के लिए यह संशोधन किया है।

नई व्यवस्था में सभी क्षेत्रों में एक समान बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार के अनुसार जिन संपत्ति श्रेणियों में वास्तविक रजिस्ट्री मूल्य मौजूदा कलेक्टर रेट से 20 प्रतिशत तक अधिक था, वहां कोई वृद्धि नहीं की गई। इसके बाद लेन-देन मूल्य और पुराने कलेक्टर रेट के अंतर के आधार पर 15 से लेकर 75 प्रतिशत तक की अलग-अलग दरों से बढ़ोतरी की गई।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस प्रक्रिया में 1,60,752 संपत्ति श्रेणियों का विश्लेषण किया गया। इनमें करीब 68.80 प्रतिशत श्रेणियों में कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाया गया, जबकि बाकी श्रेणियों में वास्तविक बाजार लेन-देन के आधार पर संशोधन किया गया। सरकार का कहना है कि इससे संपत्ति के मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ेगी और अघोषित धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

कुछ क्षेत्रों में बढ़ोतरी काफी अधिक रही। गुरुग्राम के तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में कई श्रेणियों के कलेक्टर रेट में बड़ी वृद्धि हुई है। वहीं जींद में 1 अप्रैल से लागू नई दरों में व्यावसायिक संपत्तियों के रेट में करीब 20 प्रतिशत, आवासीय में 15 प्रतिशत और कृषि भूमि में लगभग 10 प्रतिशत तक वृद्धि की रिपोर्ट सामने आई।

कलेक्टर रेट वह न्यूनतम सरकारी मूल्य है जिसके आधार पर जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए कलेक्टर रेट बढ़ने पर कई मामलों में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी लागत भी बढ़ सकती है, जिससे नए खरीदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

सरकार का कहना है कि नई दरें मनमाने ढंग से नहीं बल्कि संपत्ति की वास्तविक रजिस्ट्री और बाजार लेन-देन के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तय की गई हैं। इससे सरकारी रिकहर्ड में संपत्ति के मूल्य और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच अंतर कम करने का प्रयास किया गया है।

# नए वित्तीय वर्ष में हाईवे टोल महंगा, वाहन चालकों की जेब पर बढ़ा बोझ

जीत समाचार ब्यूरों हरियाणा। नए वित्तीय वर्ष 2026–27 की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2026 से हरियाणा में कई राष्ट्रीय राजमार्गों और टोल प्लाजा पर संशोधित टोल दरें लागू हो गईं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वार्षिक दर संशोधन प्रक्रिया के तहत टोल शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।

हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना हाईवे सहित प्रमुख मार्गों पर नई दरें 31 मार्च की मध्यरात्रि से प्रभावी हुईं। संशोधन में कारों के साथ-साथ वाणिज्यिक वाहनों, बसों और भारी वाहनों की टोल दरें भी शामिल हैं।

कुरुक्षेत्र के सैनी माजरा टोल प्लाजा पर भी 1 अप्रैल से टोल दरों में करीब 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इससे इस मार्ग से रोजाना आवागमन करने वाले वाहन चालकों और व्यावसायिक वाहनों की यात्रा लागत बढ़ गई।

वहीं अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर भी नई दरें लागू हुईं। यहां टोल भुगतान व्यवस्था में बदलाव के साथ नकद भुगतान बंद करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की व्यवस्था लागू किए जाने की जानकारी सामने आई।

इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग सालाना पास की फीस भी 1 अप्रैल से बढ़ा दी। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए वार्षिक पास की कीमत 3,000 से बढ़ाकर 3,075 कर दी गई है। यह पास पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लगभग 1,150 शुल्क प्लाजा पर मान्य है।

टोल दरों में बढ़ोतरी का सीधा असर रोजाना हाईवे का इस्तेमाल करने वाले निजी वाहन चालकों के साथ-साथ ट्रक, बस, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर पड़ने की संभावना है। परिवहन लागत बढ़ने से माल ढुलाई और यात्री परिवहन की लागत पर भी असर पड़ सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार टोल शुल्क में संशोधन एक नियमित वार्षिक प्रक्रिया है और इसमे होलसैल प्राइस ईडेक्स को आधार बनाया जाता है। इसलिए 1 अप्रैल से लागू हुई बढ़ी दरों को वार्षिक संशोधन का हिस्सा बताया गया है।

# 17 मौसम ने फिर बदली करवट, हरियाणा में बारिश-तेज हवाओं का अलर्ट

जीत समाचार चंडीगढ़/हरियाणा। हरियाणा में मार्च के अंतिम दिनों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 29 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई थी। इससे तापमान में गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद बनी, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई।

मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुआ। 1 अप्रैल के आसपास हरियाणा और आसपास के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में बादल छाने तथा कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रही। तेज हवाओं के कारण खुले क्षेत्रों में धूल उड़ने और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई।

**किसानों की बढ़ी चिंता :** गेहूं की फसल पकने और कटाई के करीब पहुंचने के समय मौसम का बिगड़ना किसानों के लिए चिंता का कारण बना। बारिश और तेज हवाओं से खेतों में खड़ी फसल के गिरने तथा दाने की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है। ऐसे में किसानों को मौसम साफ होने तक कटाई को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई।

मौसम विभाग ने उत्तर भारत में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण बारिश के साथ तेज हवाओं और गरज-चमक की संभावना जताई थी। बाद के पूर्वानुमानों में भी पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश एवं आंधी की गतिविधियों की संभावना बनी रही।

**तापमान में भी बदलाव :** बारिश और बादलों के कारण दिन के तापमान में अस्थायी गिरावट दर्ज होने की संभावना रही। हालांकि मौसम साफ होने के बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों ने किसानों और आम लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी।

# 1 अप्रैल से बदले हरियाणा के कई नियम, आम आदमी की जेब पर असर

जीत समाचार ब्यूरों हरियाणा। नए वित्तीय वर्ष 2026–27 की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2026 से हरियाणा में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी हुए। जमीन-जायदाद के कलेक्टर रेट, हाईवे टोल, न्यूनतम मजदूरी और विभिन्न सरकारी शुल्कों में बदलाव का सीधा असर आम लोगों, वाहन चालकों, श्रमिकों, कारोबारियों और संपत्ति खरीदारों पर पड़ा।

जमीन-जायदाद महंगी होने के आसाररू हरियाणा में 1 अप्रैल से संशोधित कलेक्टर रेट लागू किए गए। सरकार ने वास्तविक बाजार लेन-देन के आंकड़ों के आधार पर अलग-अलग संपत्ति श्रेणियों में बदलाव किया। कुछ श्रेणियों में कलेक्टर रेट में 15 से 75 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई, जबकि बड़ी संख्या में श्रेणियों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कलेक्टर रेट बढ़ने से संबंधित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी और अन्य खर्च बढ़ सकते हैं।

**हाईवे सफर भी महंगा:** नए वित्तीय वर्ष के साथ कई राष्ट्रीय राजमार्गों और टोल प्लाजा पर संशोधित दरें लागू हुईं। गुरुग्राम क्षेत्र के प्रमुख एक्सप्रेसवे और कुरुक्षेत्र के सैनी माजरा टोल प्लाजा पर भी दरों में बदलाव किया गया। इससे रोजाना हाईवे का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के साथ ट्रक, बस और अन्य व्यावसायिक वाहनों की लागत बढ़ी।

**फास्टैग सालाना पास की कीमत बढ़ी:** पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए फास्टैग सालाना पास की वार्षिक फीस भी 3,000 से बढ़ाकर 3,075 कर दी गई। यह बदलाव देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू हुआ और हरियाणा के वाहन चालकों पर भी इसका असर पड़ा।

**श्रमिकों के लिए राहत:** दूसरी ओर 1 अप्रैल से हरियाणा में संशोधित न्यूनतम मजदूरी लागू हुई। अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी 15,220.71, अर्ध-कुशल के लिए 16,780.74, कुशल के लिए 18,500.81 और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए 19,425.85 निर्धारित की गई। इससे कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

**नए नियमों का मिला-जुला असर:** जहां संपत्ति और परिवहन से जुड़े खर्च बढ़ने से आम नागरिक की जेब पर बोझ पड़ सकता है, वहीं न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी से श्रमिक वर्ग को राहत मिली है। कारोबारियों के लिए भी बढ़ी मजदूरी और परिवहन लागत उत्पादन एवं संचालन खर्च को प्रभावित कर सकती है। सरकार का कहना है कि कलेक्टर रेट में बदलाव का उद्देश्य संपत्ति के सरकारी मूल्यांकन को वास्तविक बाजार दरों के करीब लाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। वहीं टोल दरों में संशोधन राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू वार्षिक शुल्क संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा है।

# दूध उत्पादकों को राहत, मिल्कफेड ने बढ़ाई खरीद कीमत

जीत समाचार चंडीगढ़ 1 अप्रैल 2026। पंजाब के डेयरी किसानों के लिए राहत की खबर है। पंजाब सरकार ने मिल्कफेड पंजाब से जुड़े दूध उत्पादकों के लिए दूध की खरीद कीमत में बढ़ोतरी की है। संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी की गई हैं। सरकार के अनुसार दूध की खरीद कीमत में 10 से 15 प्रति किलोग्राम फैट की वृद्धि की गई है।

इस फैसले से मिल्कफेड से सीधे जुड़े करीब 2.5 लाख डेयरी किसानों को तत्काल लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि खरीद कीमत बढ़ने का व्यापक असर पंजाब के करीब 30 लाख दूध उत्पादकों तक पहुंच सकता है, क्योंकि अन्य सहकारी संस्थाओं और निजी दूध खरीदारों पर भी अपनी खरीद दरों में बदलाव का दबाव बनेगा।

सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई खरीद कीमत का उद्देश्य किसानों को दूध का बेहतर मेहनताना उपलब्ध कराना और डेयरी व्यवसाय को आर्थिक रूप से अधिक टिकाऊ बनाना है। पंजाब में बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों की आय डेयरी कारोबार से जुड़ी हुई है, ऐसे में खरीद दर बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है।

मिल्कफेड पंजाब द्वारा खरीद कीमत बढ़ाने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हर महीने लगभग 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि आने का अनुमान सरकार की ओर से जताया गया है। इससे पशुपालकों को चारा, पशु देखभाल और अन्य बढ़ती लागतों के बीच कुछ आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार के अनुसार यह कदम सहकारी डेयरी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। मिल्कफेड के खरीद मूल्य में वृद्धि का असर बाजार की दूसरी एजेंसियों पर पड़ने की संभावना है, जिससे दूध उत्पादकों को व्यापक स्तर पर बेहतर कीमत मिल सकती है।

# पंजाब सरकार ने उठाया 1,000 करोड़ का नया कर्ज, वित्तीय स्थिति पर सवाल

जीत समाचार चंडीगढ़ 1 अप्रैल 2026। पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 की शुरुआत में विकास कार्यों और सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से नया कर्ज उठाने का सिलसिला जारी रखा है। अप्रैल 2026 में राज्य सरकार द्वारा 1,000 करोड़ के नए कर्ज को लेकर विपक्ष ने सरकार की वित्तीय नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी सरकार द्वारा लगातार बाजार से उधार लिए जाने को लेकर राज्य की आर्थिक स्थिति चर्चा में रही है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमानों के अनुसार पंजाब सरकार ने ऋण चुकाने को छोड़कर कुल 1,66,711 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया है। इसके मुकाबले उधारी को छोड़कर राज्य की प्राप्तियां करीब 1,26,740 करोड़ रहने का अनुमान है। बजट में करीब 38,471 करोड़ की शुद्ध उधारी का प्रावधान रखा गया है।

लगातार बढ़ती उधारी को लेकर सबसे बड़ा सवाल राज्य के कुल कर्ज के बोझ को लेकर उठ रहा है। वर्ष 2025–26 के अंत तक पंजाब का बकाया कर्ज करीब 4.17 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। यह पिछले वित्तीय वर्ष के लगभग 3.82 लाख करोड़ के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि है।

हालांकि सरकार का पक्ष है कि बाजार से लिया जा रहा कर्ज विकास कार्यों और पूंजीगत परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जुलाई 2026 में भी सरकार ने 1,000 करोड़ का बाजार ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे पूंजीगत ढांचे और विकास योजनाओं के वित्तपोषण से जोड़ा गया था।

विपक्षी दलों का आरोप है कि लगातार कर्ज लेने से राज्य पर ब्याज और ऋण अदायगी का बोझ बढ़ रहा है तथा आने वाले वर्षों में इसका दबाव विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है। वहीं सरकार का तर्क है कि निर्धारित वित्तीय सीमाओं के भीतर उधारी लेकर विकास कार्यों को गति दी जा रही है।

वित्तीय जानकारों के लिए असली चिंता यह है कि नई उधारी का कितना हिस्सा उत्पादक परिसंपत्तियों और राजस्व बढ़ाने वाली परियोजनाओं में लगाया जा रहा है और कितना हिस्सा पुराने दायित्वों तथा नियमित खर्चों को पूरा करने में जा रहा है। लगातार बढ़ते कर्ज के बीच पंजाब सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना, खर्चों को नियंत्रित करना और ऋण का प्रभावी प्रबंधन आने वाले समय में बड़ी चुनौती बना रहेगा।

# लुधियाना में औद्योगिक निवेश की उम्मीद, जोगिंद्रा ग्रुप करेगा 1,100 करोड़ का विस्तार

जीत समाचार लुधियाना। पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1 अप्रैल 2026 को बड़ी निवेश खबर सामने आई। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि जोगिंद्रा ग्रुप पंजाब में अपने कारोबार के विस्तार पर करीब 1,100 करोड़ निवेश करेगा। यह निवेश मुख्य रूप से स्टील निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किया जाएगा।

प्रस्तावित निवेश में करीब 700 करोड़ स्टील कारोबार में लगाए जाएंगे। यह विस्तार जोगिंद्रा कास्टिंग्स और वर्धमान आदर्श जैसी इकाइयों के माध्यम से किया जाना है। इसके अलावा करीब 400 करोड़ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किए जाने की योजना है।

मंत्री के अनुसार इस विस्तार से समूह का कारोबार मौजूदा करीब 3,000 करोड़ से बढ़कर 5,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं कर्मचारियों की संख्या करीब 1,800 से बढ़कर 3,000 होने की संभावना जताई गई है। इससे प्रत्यक्ष रोजगार के साथ-साथ परिवहन, सप्लाई, इंजीनियरिंग और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी समूह अपनी क्षमता बढ़ाने की तैयारी में है। मौजूदा करीब 37 मेगावाट क्षमता को बढ़ाकर 120 मेगावाट करने की योजना बताई गई है। इससे औद्योगिक विकास के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की सरकार की नीति को भी बल मिलने की उम्मीद है।

हालांकि निवेश का बड़ा हिस्सा मंडी गोबिंदगढ़ और पंजाब के स्टील क्षेत्र से संबंधित है, इसका प्रभाव लुधियाना सहित आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों पर भी पड़ने की संभावना है। लुधियाना पहले से ही इंजीनियरिंग, साइकिल, अहटो पार्ट्स और मशीनरी उद्योगों का बड़ा केंद्र है। ऐसे में स्टील और ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश से औद्योगिक सप्लाई चेन को मजबूती मिल सकती है।

पंजाब सरकार ने इस निवेश को राज्य में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सरकार का कहना है कि उद्योगों के विस्तार से पंजाब की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और राज्य को एक मजबूत औद्योगिक एवं ग्रीन-एनर्जी हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

# चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर धमाका, पुलिस ने शुरू की जांच

चंडीगढ़ एजेंसी 1 अप्रैल 2026। चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर बुधवार, 1 अप्रैल 2026 की शाम धमाके की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस ने विस्फोट में किसी तरह के क्रूड-टाइप डिवाइस के इस्तेमाल की आशंका जताई।

पुलिस के अनुसार धमाका शाम करीब 5 बजे के आसपास हुआ। घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, क्राइम ब्रांच, अहृपरेशन सेल और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से नमूने एकत्र किए गए ताकि विस्फोट में इस्तेमाल सामग्री और उसके स्रोत का पता लगाया जा सके।

**इलाके को किया गया सील :** धमाके के बाद पुलिस ने भाजपा कार्यालय के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया और आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी। मौके पर फोरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी, ताकि घटना से पहले और बाद में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

चंडीगढ़ की एसएसपी कनवर्दीप कौर ने बताया कि पुलिस को करीब 5 बजे भाजपा कार्यालय के पास विस्फोट जैसी आवाज सुनाई देने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम लगभग 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हुआ कि कार्यालय के बाहर एक छोटा क्रूड-टाइप उपकरण फेंका गया था।

**वाहनों को नुकसान, कोई जनहानि नहीं :** धमाके की तीव्रता कम होने के कारण किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं मिली। हालांकि, घटनास्थल के आसपास खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक एक कार की विंडशील्ड क्षतिग्रस्त हुई और आसपास के क्षेत्र में विस्फोट के प्रभाव के निशान भी मिले।

भाजपा नेताओं ने घटना पर चिंता जताते हुए पुलिस से मामले की गहन जांच की मांग की। पार्टी के प्रदेश मीडिया सेल से जुड़े नेता विनीत जोशी ने कहा कि धमाके के बाद दीवार पर कुछ निशान दिखाई दिए और घटना की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

**सुरक्षा एजेंसियां हुईं सक्रिय :** घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी। मौके से मिले सुरागों, फोरेंसिक नमूनों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि विस्फोट किस प्रकार किया गया और इसके पीछे कौन लोग थे।

प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने दो संदिग्धों की तलाश शुरू की थी। घटना के बाद चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई।

**बाद की जांच में सामने आए अहम तथ्य :** घटना के अगले दिन की जांच में पुलिस ने इसे ग्रेनेड हमले के रूप में आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच भी शुरू हुई। बाद की रिपोर्टों में इस मामले में गिरफ्तारियां और कथित आतंकी मॉड्यूल से जुड़े पहलू सामने आए। हालांकि, 1 अप्रैल की प्रारंभिक खबर के समय इन बाद की जांच संबंधी जानकारियों की पुष्टि नहीं हुई थी।

घटना ने चंडीगढ़ के राजनीतिक और सुरक्षा माहौल में चिंता बढ़ा दी है। पुलिस और जांच एजेंसियां विस्फोट के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी रहीं।

Samuh Samaj Sangathan (SSS)
अभी नही तो कभी नहीं
मानवता की रक्षा एवं सुरक्षित करने का मौका।
सच्चाई से देश सेवा।
मदद लेने और मदद देने के लिए सम्पर्क करें।
9803025111,7986209181,9872081907,9872177784,
7973368960
संगठन का Account No. 65022011000577
IFSC CODE : BKID0006502
BANK OF INDIA
PAYTM ACCOUNT NO.
9815599888,9988340624,9041090470

# पंजाब में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वे शुरू, सीएम मान बोले समान विकास की दिशा में बड़ा कदम

जीत समाचार ब्यूरों चंडीगढ़ 1 अप्रैल 2026। पंजाब सरकार ने राज्य में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस सर्वे का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न सामाजिक वर्गों की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करना है, ताकि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ जरूरतमंद लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से अलग-अलग वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सरकार अब व्यवस्थित तरीके से यह जानकारी जुटाएगी, जिससे भविष्य में नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं वास्तविक जरूरतों के आधार पर तैयार की जा सकें।

सरकार के अनुसार सर्वेक्षण के दौरान परिवारों से उनकी सामाजिक, आर्थिक और अन्य संबंधित परिस्थितियों के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। इस प्रक्रिया के आधार पर यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों और समुदायों को सरकारी सहायता एवं विकास योजनाओं की अधिक आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आवास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में किया जा सकता है। इससे सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं की बेहतर तस्वीर भी मिल सकेगी।

सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करने और जरूरतमंद वर्गों तक सरकारी सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे समान अवसर और संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

पंजाब सरकार का कहना है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित वास्तविक आंकड़े उपलब्ध होने से प्रशासन को योजनाएं बनाने और उनके क्रियान्वयन की निगरानी में भी सुविधा होगी। सरकार का दावा है कि सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी वर्ग को बांटना नहीं, बल्कि विकास की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझना और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के हर नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर और सम्मानजनक जीवन मिलना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सर्वेक्षण भविष्य की नीतियों को अधिक लक्ष्य आधारित बनाने में उपयोगी साबित होगा।

सरकार की इस पहल को पंजाब में सामाजिक न्याय और योजनाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

# हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 15 मई से सीधी उड़ान, लुधियाना को बड़ी सौगात

जीत समाचार लुधियाना। पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना और आसपास के लोगों के लिए हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एअर इंडिया ने घोषणा की है कि हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सीधी वाणिज्यिक उड़ान सेवा 15 मई 2026 से शुरू की जाएगी। हलवारा से उड़ान सेवा शुरू करने वाली एअर इंडिया पहली एयरलाइन होगी।

एअर इंडिया के अनुसार दिल्ली और हलवारा के बीच रोजाना दो उड़ानें संचालित की जाएंगी। इन उड़ानों के लिए एयरबस ।320 फैमिली के विमान इस्तेमाल किए जाएंगे। नई हवाई सेवा से लुधियाना, खन्ना, मोगा, बरनाला और आसपास के औद्योगिक एवं कारोबारी क्षेत्रों के यात्रियों को दिल्ली आने-जाने के लिए एक नया और तेज विकल्प मिलेगा।

**दिन में दो बार मिलेगी उड़ान :** 15 मई से लागू कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली से हलवारा के लिए पहली उड़ान ए 481 सुबह 5:55 बजे रवाना होकर 7:05 बजे हलवारा पहुंचेगी। वापसी की उड़ान ए 482 सुबह 7:55 बजे हलवारा से रवाना होकर 9:10 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

दूसरी सेवा में ए 483 दिल्ली से दोपहर 12:55 बजे रवाना होकर 2:10 बजे हलवारा पहुंचेगी, जबकि ए 44 हलवारा से दोपहर 2:40 बजे रवाना होकर 3:55 बजे दिल्ली पहुंचेगी। ये उड़ानें सप्ताह के सभी सातों दिन संचालित होने के लिए निर्धारित की गई हैं।

**कारोबार और उद्योग को मिलेगा फायदा :** लुधियाना देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में कारोबारी, उद्योगपति और निर्यातक दिल्ली सहित देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में हलवारा से सीधी दिल्ली उड़ान शुरू होने से कारोबारियों के लिए यात्रा का समय कम होने और व्यापारिक संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।

लुधियाना के लोगों को लंबे समय से अपने शहर के नजदीक नियमित हवाई सेवा का इंतजार था। हलवारा एयरपोर्ट से नियमित उड़ान शुरू होना इस इंतजार को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

**दिल्ली के जरिए विदेशों तक आसान पहुंच :** इस सेवा की एक बड़ी खासियत यह है कि यात्री दिल्ली पहुंचकर एअर इंडिया के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। कंपनी ने बताया है कि हलवारा-दिल्ली सेवा को इस तरह समयबद्ध किया गया है कि यात्रियों को दिल्ली के जरिए लंदन, बर्मिंघम, पेरिस, मिलान और रोम जैसे यूरोपीय शहरों के लिए आगे की यात्रा में सुविधा मिल सके।

एअर इंडिया के मुताबिक यात्रियों को एक ही टिकट पर आगे की कनेक्टिंग यात्रा और सामान की एफ-चेक सुविधा मिल सकती है। इससे पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधाजनक हो सकती है।

**लंबे इंतजार के बाद मिली हवाई कनेक्टिविटी :** हलवारा एयरपोर्ट पर नागरिक विमान सेवा शुरू होना लुधियाना के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित परियोजना रही है। एयरपोर्ट के नागरिक टर्मिनल को मौजूदा भारतीय वायुसेना स्टेशन के विस्तार के साथ विकसित किया गया है। इसके शुरू होने से लुधियाना को राष्ट्रीय विमानन नेटवर्क में सीधे जोड़ने की उम्मीद मजबूत हुई है।

व्यापारिक संगठनों और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली की सीधी उड़ान के बाद हलवारा से मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और अन्य प्रमुख शहरों के लिए भी उड़ान सेवाओं का विस्तार होगा। इससे लुधियाना के उद्योग, व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।

**पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र के लिए अहम कदम :** हलवारा से नियमित हवाई सेवा शुरू होने को केवल लुधियाना ही नहीं, बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आसपास के जिलों के लोगों को दिल्ली पहुंचने के लिए सड़क या रेल परिवहन पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिलेगा।

एअर इंडिया ने हलवारा को अपने नेटवर्क में शामिल करते हुए इसे पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र को दिल्ली और उसके जरिए अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

15 मई से शुरू होने वाली यह हवाई सेवा लुधियाना के आर्थिक, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है।

# हिमाचल में बिजली हुई सस्ती, 1 अप्रैल से नई दरें लागू

जीत समाचार ब्यूरों शिमला। हिमाचल प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। 1 अप्रैल 2026 से राज्य में नई बिजली दरें लागू हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए औसत बिजली आपूर्ति लागत को पिछले वर्ष के 6.76 प्रति यूनिट से घटाकर 6.75 प्रति यूनिट निर्धारित किया है।

नई दरों से घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बोझ कम होने की उम्मीद है। प्रदेश में पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा भी जारी रखी गई है। इससे कम खपत वाले परिवारों को विशेष राहत मिलने की संभावना है।

बिजली दरों में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बिजली की लागत को लेकर चिंतित रहे हैं। नियामक आयोग द्वारा आपूर्ति लागत में मामूली कमी किए जाने से राज्य की बिजली व्यवस्था में लागत नियंत्रण पर भी ध्यान दिया गया है।

नई टैरिफ व्यवस्था के तहत अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें उनकी खपत और कनेक्शन की श्रेणी के आधार पर निर्धारित की गई हैं। घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू दरों में अंतर रखा गया है।

राज्य सरकार और बिजली विभाग का प्रयास है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ बिजली वितरण व्यवस्था को भी आर्थिक रूप से मजबूत रखा जाए। हिमाचल में जलविद्युत उत्पादन की बड़ी क्षमता होने के बावजूद बिजली खरीद, ट्रांसमिशन और वितरण से जुड़ी लागत का असर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। ऐसे में टैरिफ में मामूली कमी को उपभोक्ताओं के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा हिमाचल सरकार की प्रमुख राहत योजनाओं में शामिल है। नई दरों के लागू होने के बाद कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलता रहेगा।

# हिमाचल में बाहरी वाहनों पर नई एंट्री फीस लागू, 55 बैरियरों पर वसूली शुरू

जीत समाचार ब्यूरों शिमला 1 अप्रैल 2026। हिमाचल प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष के साथ 1 अप्रैल 2026 से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर नई एंट्री फीस व्यवस्था लागू कर दी गई। राज्य के प्रवेश मार्गों पर बनाए गए 55 बैरियरों के माध्यम से यह शुल्क वसूला जाना शुरू हुआ। सरकार का उद्देश्य बाहरी वाहनों से राजस्व जुटाने के साथ-साथ राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना है।

नई व्यवस्था के तहत हिमाचल में प्रवेश करने वाले 5 से 12 सीटर निजी वाहनों पर 100 का प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया। हालांकि, सभी वाहनों पर समान शुल्क लागू नहीं है और वाहन की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं। 12 सीटर तक की टैक्सियों को इस शुल्क से छूट दी गई है।

सरकार ने प्रवेश शुल्क की वसूली के लिए प्रदेश के विभिन्न सीमावर्ती मार्गों पर बैरियरों की व्यवस्था की है। इन स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके और शुल्क वसूली में पारदर्शिता बनी रहे।

नई व्यवस्था को लेकर पंजाब और हिमाचल के बीच विवाद भी सामने आया। पंजाब के किसान संगठनों, ट्रांसपोर्टरों और टैक्सी ऑपरेटरों ने हिमाचल के प्रवेश शुल्क का विरोध किया।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हिमाचल आने-जाने वाले पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से परिवहन लागत बढ़ेगी। इसके विरोध में पंजाब-हिमाचल सीमा पर वाहनों की आवाजाही रोकने का ऐलान किया गया था।

प्रदर्शन के कारण दोनों राज्यों की सीमा पर कुछ स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। पंजाब के संगठनों ने हिमाचल सरकार से इस शुल्क को वापस लेने की मांग की। उनका तर्क था कि हिमाचल में आने वाले पर्यटक राज्य की अर्थव्यवस्था में पहले ही होटल, परिवहन, पर्यटन और अन्य सेवाओं के माध्यम से बड़ा योगदान देते हैं।

दूसरी ओर हिमाचल सरकार का तर्क है कि बाहरी वाहनों की आवाजाही के प्रबंधन और राज्य में बेहतर निगरानी व्यवस्था के लिए यह शुल्क आवश्यक है। सरकार का मानना है कि शुल्क व्यवस्था से राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और प्रवेश मार्गों पर वाहनों का बेहतर रिकहर्ड भी तैयार किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था का असर खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों से हिमाचल आने वाले निजी वाहन चालकों पर पड़ सकता है। पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही प्रवेश बैरियरों पर वाहनों की संख्या बढ़ने की संभावना है, इसलिए सरकार के सामने शुल्क वसूली के साथ यातायात को सुचारू बनाए रखने की भी चुनौती रहेगी।

# हिमाचल में अप्रैल से SIR की तैयारी, मतदाता सूचियों का होगा विशेष पुनरीक्षण

जीत समाचार ब्यूरों शिमला। हिमाचल प्रदेश में मतदाता सूचियों को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए एसआईआर की तैयारी शुरू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की योजना के अनुसार हिमाचल समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल २०२६ से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी थी।

एसआईआर के दौरान मतदाता सूचियों में दर्ज नाम, पते और अन्य विवरणों का व्यापक स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं का नाम सूची में सुनिश्चित करना तथा अपात्र, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं से जुड़े रिकहर्ड को दुरुस्त करना है।

हिमाचल में निर्वाचन विभाग के स्तर पर इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही थीं। बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से मतदाताओं की जानकारी के सत्यापन और दस्तावेजों से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाया जाना है। प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को अपने नाम और विवरण की जांच करने का अवसर भी मिलेगा।

विशेष पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं के रिकहर्ड में किसी प्रकार की गलती होगी, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा मृत्यु या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी पुनरीक्षण का हिस्सा होगी।

निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं से अपील की गई है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते संबंधित निर्वाचन अधिकारी या निर्धारित माध्यम से सुधार के लिए आवेदन करें।

हिमाचल में आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सही और अद्यतन मतदाता सूची स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। ऐसे में एसआईआर के दौरान प्रशासन के साथ-साथ राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी।

# बजट सत्र अंतिम चरण में, विधानसभा में सरकार की योजनाओं पर चर्चा

जीत समाचार एजेंसी शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2 अप्रैल 2026 तक निर्धारित होने के कारण 1 अप्रैल को सदन की कार्यवाही अंतिम चरण में पहुंच गई। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया था और 30 मार्च को बजट पारित किया जा चुका था। अंतिम दिनों में सरकार की योजनाओं, विभागीय कार्यप्रणाली और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा प्रमुख रही।

बजट सत्र के दौरान सरकार ने कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे को प्राथमिकता देने की बात कही। सरकार की ओर से बजट में रोजगार सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न प्रावधानों की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट पर सत्ता पक्ष ने सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को रेखांकित किया, जबकि विपक्ष ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज और सरकार के कई फैसलों को लेकर सवाल उठाए। विधानसभा में दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस भी देखने को मिली।

बजट पारित होने के बाद सत्र के अंतिम चरण में विभागवार योजनाओं और बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा महत्वपूर्ण रही। विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे स्थानीय मुद्दे भी सदन में उठाए।

सरकार की ओर से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि बजट का फोकस केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर रोजगार, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर है। वहीं विपक्ष ने योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर सरकार से जवाब मांगा।

सत्र के अंतिम दिन नजदीक आने के साथ विधानसभा परिसर में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज रहीं। बजट पारित होने के बाद अब सरकार के सामने घोषित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने की चुनौती है।

# नए वित्तीय वर्ष में शराब महंगी, हिमाचल में बदली आबकारी व्यवस्था

जीत समाचार शिमला। हिमाचल प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष 2026–27 की शुरुआत के साथ शराब उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। 1 अप्रैल 2026 से शराब की संशोधित दरें लागू हो गईं। आबकारी एवं कराधान विभाग ने विभिन्न श्रेणियों की शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अंग्रेजी शराब के कई ब्रांडों पर 100 तक की वृद्धि, जबकि नियमित ब्रांडों पर करीब 10 से 30 तक की बढ़ोतरी की गई है।

नई दरें वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। विभाग ने 2026–27 के लिए शराब की विभिन्न श्रेणियों और ब्रांडों की अधिकतम खुदरा कीमतों की सूची भी जारी की है।

नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री और लाइसेंस व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। हिमाचल सरकार ने पहली बार खुदरा शराब ठेकों के आवंटन के लिए ई-नीलामी व्यवस्था लागू की है। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए खुदरा शराब इकाइयों की नीलामी अहनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की गई, जिसका उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और राजस्व में सुधार करना है।

विभाग ने शराब विक्रेताओं के लिए सभी ब्रांडों की दर सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है। इससे ग्राहकों को निर्धारित कीमत की जानकारी मिल सकेगी और मनमाने दाम वसूलने की शिकायतों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

सरकार के लिए आबकारी राजस्व राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। नई नीति और संशोधित दरों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य राजस्व संग्रह बढ़ाने के साथ शराब कारोबार को अधिक व्यवस्थित करना है। वहीं उपभोक्ताओं पर कीमत बढ़ने का सीधा असर पड़ेगा।

पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ हिमाचल में शराब की मांग भी बढ़ती है। ऐसे में नई दरों का असर स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ-साथ प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के खर्च पर भी पड़ सकता है।

# 'धुरंधर 2' की बॉक्स ऑफिस पर धूम, रणवीर सिंह का जलवा बरकरार

मुंबई। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ''धुरंधरः द रिवेंज'' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। 19 मार्च को रिलीज हुई आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस एक्शन-स्पाई थ्रिलर ने महज कुछ ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं।''31 मार्च तक फिल्म का दुनियाभर का कलेक्शन करीब 1,400 करोड़ के पार पहुंच गया था।''

फिल्म की सफलता ने रणवीर सिंह के स्टारडम को एक बार फिर मजबूत किया है। फिल्म में रणवीर के साथ ''आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन'' भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। कहानी और एक्शन सीक्वेंस को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला है।

### बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत पकड़

दूसरे सप्ताह में पहुंचने के बावजूद फिल्म की कमाई ने निर्माताओं और ट्रेड विशेषज्ञों को प्रभावित किया है। रिपोर्टों के मुताबिक फिल्म ने 12वें दिन तक दुनियाभर में लगभग ''1,390 करोड़'' का आंकड़ा पार कर लिया था और इसके बाद 1,400 करोड़ के क्लब में प्रवेश कर गई।

फिल्म की घरेलू कमाई भी लगातार मजबूत बनी हुई है। उपलब्ध बहक्स अहफिस आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च तक भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन ''1,108 करोड़ से अधिक'' बताया गया।

रणवीर सिंह की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल

'धुरंधरः द रिवेंज' की सफलता रणवीर सिंह के करियर के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिल्म के पहले भाग ''धुरंधर'' की सफलता के बाद सीक्वल ने भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाबी हासिल की है। दोनों फिल्मों की सफलता ने रणवीर को बहक्स अहफिस के सबसे चर्चित सितारों में फिर से ला खड़ा किया है।

फिल्म के लगातार मजबूत प्रदर्शन के कारण अब ट्रेड जगत की नजर इस बात पर है कि यह कितने बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अपने नाम करती है। शुरुआती आंकड़ों के आधार पर फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में तेजी से ऊपर पहुंच रही है।

### दर्शकों में बना हुआ है क्रेज

फिल्म के एक्शन, कहानी और रणवीर सिंह के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा बनी हुई है। सिनेमाघरों में दर्शकों की मौजूदगी ने फिल्म के कारोबार को मजबूती दी है। आने वाले दिनों में फिल्म के सामने नई रिलीज फिल्मों की चुनौती होगी, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए इसके कारोबार को लेकर उम्मीदें बनी हुई हैं।

# 'रामायण' को लेकर बढ़ा क्रेज, रणबीर कपूर के राम अवतार का इंतजार

मुंबई। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म को लेकर निर्माताओं ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है और इसके विजुअल्स तथा तकनीकी स्तर को लेकर पहले से ही चर्चा बनी हुई है।

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल स्तर बताया जा रहा है। 'रामायण' को दो भागों में रिलीज करने की योजना है। पहला भाग दीपावली 2026 के दौरान और दूसरा भाग दीपावली 2027 के आसपास रिलीज किए जाने की योजना बताई गई है। फिल्म की कहानी में भगवान राम के जीवन, अयोध्या से वनवास और आगे की महत्वपूर्ण घटनाओं को बड़े सिनेमाई पैमाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

### रणबीर के लुक ने बढ़ाई उत्सुकता

रणबीर कपूर के भगवान राम के रूप को लेकर प्रशंसकों में खासा उत्साह है। फिल्म के निर्माताओं ने किरदारों के लुक और विजुअल डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया है। रणबीर का राम के रूप में चयन सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।

फिल्म में यश भगवान राम के भाई लक्ष्मण नहीं, बल्कि रावण की भूमिका निभा रहे हैं। सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में दिखाई देंगे, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे।

### हॉलीवुड तकनीकी टीम भी जुड़ी

'रामायण' को भारतीय सिनेमा की बड़ी अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल किया जा रहा है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की टीम काम कर रही है। निर्माताओं का लक्ष्य भारतीय पौराणिक कथा को आधुनिक तकनीक और बड़े पर्दे के भव्य अनुभव के साथ दर्शकों तक पहुंचाना है।

फिल्म की कहानी और प्रस्तुति को लेकर निर्माताओं ने गोपनीयता बनाए रखी है। यही वजह है कि फिल्म से जुड़ी हर नई जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

### दर्शकों को रिलीज का इंतजार

रणबीर कपूर के प्रशंसकों के साथ-साथ पौराणिक फिल्मों में रुचि रखने वाले दर्शक भी 'रामायण' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का पहला भाग 2026 में सिनेमाघरों में आने की उम्मीद है। रिलीज से पहले फिल्म का प्रचार अभियान तेज होने के साथ इसके ट्रेलर और अन्य सामग्री को लेकर भी दर्शकों की उत्सुकता बढ़ने की संभावना है।

# 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की वापसी, हॉरर-कॉमेडी को लेकर उत्साह

मुंबई। बॉलीवुड में अपनी सफल कहमेडी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ लौट रहे हैं। दोनों की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह बना हुआ है। हहरर और कहमेडी के मिश्रण वाली यह फिल्म दर्शकों को डराने के साथ-साथ हंसाने की कोशिश करेगी।

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी इससे पहले 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला', 'भूल भुलैया' और 'भूल भुलैया 2' जैसी चर्चित फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन कर चुकी है। ऐसे में दोनों की लंबे समय बाद वापसी को लेकर फिल्म प्रेमियों की दिलचस्पी स्वाभाविक है।

**हॉरर के साथ कहमेडी का तड़का :** 'भूत बंगला' की कहानी में हॉरर के साथ कॉमेडी को प्रमुखता दी गई है। फिल्म में अक्षय कुमार एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जिसके आसपास रहस्यमय और हास्यपूर्ण घटनाएं घटती हैं। निर्माताओं ने फिल्म के कथानक और किरदारों को लेकर काफी गोपनीयता बरती है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ी हुई है।

फिल्म में तब्बू, परेश रावल और वामिका गब्बी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगी। अक्षय और परेश रावल की जोड़ी को दर्शक पहले भी कई सफल कॉमेडी फिल्मों में पसंद कर चुके हैं। इसलिए इस फिल्म में दोनों की मौजूदगी को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं।

**प्रियदर्शन की खास शैली पर नजर :** प्रियदर्शन की फिल्मों में हास्य, पारिवारिक मनोरंजन और परिस्थितिजन्य कहमेडी की खास शैली देखने को मिलती रही है। 'भूत बंगला' में इसी शैली को हॉरर के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। फिल्म के जरिए निर्देशक एक ऐसा मनोरंजन पैकेज पेश करना चाहते हैं, जिसमें रोमांच, हास्य और रहस्य तीनों का मेल हो।

**अक्षय के प्रशंसकों को बड़ी उम्मीद :** अक्षय कुमार लंबे समय से कहमेडी फिल्मों के लिए दर्शकों की पहली पसंद रहे हैं। 'भूत बंगला' के जरिए अभिनेता एक बार फिर अपने कॉमिक अंदाज में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी को लेकर प्रशंसकों के बीच चर्चा बनी हुई है।

फिल्म की रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर इसे अन्य बड़ी फिल्मों से भी मुकाबला करना होगा। हालांकि अक्षय कुमार की लोकप्रियता और प्रियदर्शन के निर्देशन को देखते हुए फिल्म से अच्छी शुरुआत की उम्मीद की जा रही है।

**मनोरंजन से भरपूर होने की उम्मीद :** फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका हॉरर-कॉमेडी जॉनर है, जो परिवार और युवा दर्शकों दोनों को सिनेमाघरों तक खींचने की क्षमता रखता है। अब नजर इस बात पर है कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की यह वापसी दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।